गोरखपुर से प्रकाशित

RNI Reg. NO. UPBIL/2023/87841

SI न्यूज़

साप्ताहिक
स्वदेशी इनक्रेडिबल

Web:www.sinews.in/E-mail: info@sinews.in

सिर्फ सच के साथ...

वर्ष : 02 अंक: 42 | गोरखपुर रविवार 06 अप्रैल 2025 | मूल्य- 02 रूपया | पृष्ठ - 8

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवनशैली अपनाएं लोग, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी: राष्ट्रपति

➤ पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकास की भारतीय विरासत का आधार 'पोषण है, शोषण नहीं; संरक्षण है, उन्मूलन नहीं'।

एजेंसी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से अपील की है कि वे पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील जीवनशैली को अपनाएं। राष्ट्रपति ने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण हो सकेगा, बल्कि इससे पर्यावरण ज्यादा जीवंत बनाया जा सकता है। शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बातें कहीं। राष्ट्रपति ने कहा कि भावी पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकास की भारतीय विरासत का आधार 'पोषण है, शोषण नहीं; संरक्षण है, उन्मूलन नहीं'। इस विरासत को ध्यान में रखते हुए हम एक विकसित भारत की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं।' राष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग सदियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते आए हैं और वे अपने जीवन के हर पहलू में आसपास के पर्यावरण, पौधों और जानवरों का ख्याल रखते आए हैं। उन्होंने कहा, 'हमें उनकी जीवनशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जब पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में आदिवासी समुदाय की जीवनशैली और भी अनुकरणीय हो जाती है।' राष्ट्रपति ने लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक और संवेदनशील जीवनशैली अपनाने को कहा ताकि पर्यावरण न केवल संरक्षित हो बल्कि बढ़े और पर्यावरण अधिक जीवंत हो सके।

रामगंज नगर पंचायत के चेयरमैन राकेश सिंह ने पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येन्द्र बारी का किया भव्य स्वागत

○ सरकार के आठ वर्ष प्रदेश के उत्थान, उन्नति एवं जनकल्याण के लिए समर्पित : सत्येन्द्र बारी

प्रतापगढ़ ।प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के आठ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रतापगढ़ ज़िले के रामगंज नगर पंचायत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पिछड़ा आयोग के सदस्य सत्येन्द्र बारी मौजूद रहे।श्री सत्येन्द्र जी ने बताया कि भाजपा सरकार में हर वर्ग का समुचित विकास हो है। आज योगी की सरकार में किसी की इतनी हिम्मत नहीं की बहन बेटी को गलत निगाह से देखे ।श्री सत्येन्द्र जी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भारत माता की प्रतिमा दे कर सम्मानित किया ।कार्यक्रम में नगर

पंचायत के चेयरमैन राकेश सिंह,सभासद महेंद्र जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

मुख्यमंत्री यादव ने 23,162 श्रमिकों के परिवारों को 505 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की

एजेंसी

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत 23,162 श्रमिकों के परिवारों को 505 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि हस्तांतरित की है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में यादव ने कहा कि नीति आयोग की पहल के बाद गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को भी संबल योजना के तहत लाया गया है और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। यादव ने कहा, वे अब आम कर्मचारियों के समान लाभ पाने के पात्र हैं। लाभार्थियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सब्सिडी वाले अनाज के लिए राशन कार्ड भी मिलते हैं। गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रमिकों के परिवारों को चार लाख रुपये, प्राकृतिक मृत्यु पर दो लाख रुपये, स्थायी विकलांगता पर दो लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में पांच हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है।

पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए सभी पत्रकार संगठनों ने दिखाया दमखम

जिलाधिकारी कार्यालय में को ज्ञापन सौंप, किया एफआईआर दर्ज करते हुए निलंबन की मांग

गोरखपुर। पत्रकार पवन गुप्ता को प्रतीक्षारत तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह द्वारा दिए गए गाली,धमकी व फर्जी एससी एसटी मुकदमे में फसाने का मामला तूल पकड़ लिया है। दिनांक 7 अप्रैल को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क से सैकड़ो की तादाद में पवन गुप्ता सहित सैकड़ों पत्रकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर गालीबाज तहसीलदार के ऊपर एफआईआर दर्ज करने एवं निलंबित करने का ज्ञापन सौंपा। बताते चलें कि 2 अप्रैल की शाम लगभग 7:30 बजे पत्रकार पवन गुप्ता के व्हाट्सएप नंबर पर अपने आप को ध्रुवेश कुमार सिंह तहसीलदार गोरखपुर सदर कहते हुए अंधाधुंध गालियों की बौछार लगा दी थी, उन्होंने फर्जी एससी एसटी मुकदमे में फसाने की धमकी देते हुए तहसील में कवरेज हेतु घुसने पर पीटने की धमकी दी थी। उपरोक्त घटना का जब ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसको लेकर जिले से तहसील एवं प्रदेश स्तर पर पत्रकारों में आक्रोश फैल गया। प्रतीक्षारत तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह के अमानवीय कृत से जिले से तहसील एवं प्रदेश स्तर तक के सभी पत्रकार संगठन कड़ी निंदा करते हुए प्रत्येक अपने तहसीलों में अधिकारियों को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन देते समय अरविंद राय,कुन्दन उपाध्याय,पंकज श्रीवास्तव, शतीस पाण्डेय,दामोदर उपाध्याय,कौशल त्रिपाठी,मन्नवर रिजवी,राज अनंत पाण्डेय, ओमकार धर द्विवेदी, प्रिंस पाण्डेय,अंगद प्रजापति, आशीष मिश्रा,सुनील तिवारी, निखिल गुप्ता, सूर्य प्रकाश गुप्ता, धीरेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र पटवा,चन्द्र प्रकाश मणि, शतीस शुक्ला,आदर्श श्रीवास्तव, सूरज शर्मा,जेपी प्रजापति, मुकेश प्रजापति,यूसुफ, फैयाज अहमद,अनिल गुप्ता, विजय गुप्ता, राहुल सहित सैकड़ो पत्रकार उपस्थित रहे।

Our Respected Guest

Mahamandleshwar Kankeshwari Nand Giri
Kinnar Akhada

Pushdant Jain
Social Worker

Ravi Kishan Shukla
MP, Gorakhpur

Dr. R.M.D. Agrawal
MLC

Dr. Dharmendra Singh
MLC

Vipin Singh
MLA, Rural Gorakhpur

Dr. Manglesh Srivastava
Mayor, Gorakhpur

Pradeep Shukla
MLA, Sahjanwa, Gorakhpur

Rajesh Tripathi
MLA, Chillupar, Gorakhpur

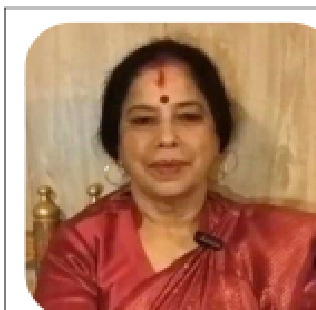
Dr. Satya Pandey
Ex. Mayor of Gorakhpur

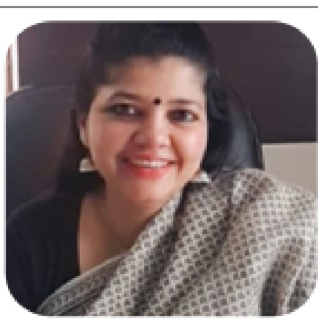
Charu Choudhary
Vice President of Women Commission, UP

Prashant Srivastava
ADI, Gorakhpur

Gaurav Singh Sogarwal
Municipal Commissioner (IAS), Gorakhpur

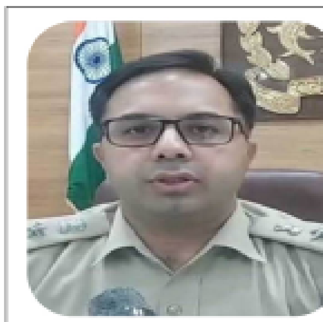
Dr. Gaurav Grover
SSP, Gorakhpur

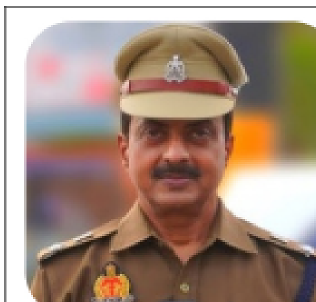
Sanjay Kumar
SP Traffic, Gorakhpur

Dr. Ashutosh Dubey
Ex. CMO, Gorakhpur

Rajesh Gupta
Ex. President Mahanagar, Gorakhpur

Devesh Srivastava
President Mahanagar, Gorakhpur

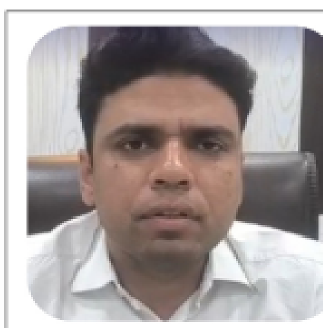
Amit Kumar Singh
PRD

Ramesh Ji
RRS, Gorakhpur

Best Wishes for SI News

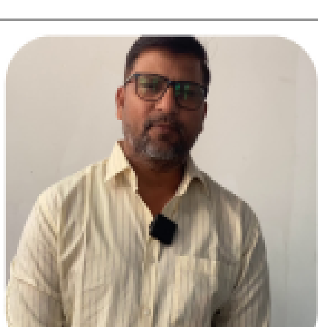
Dheeraj Gupta
Sarv Samaj Sewa Santhan, Gorakhpur

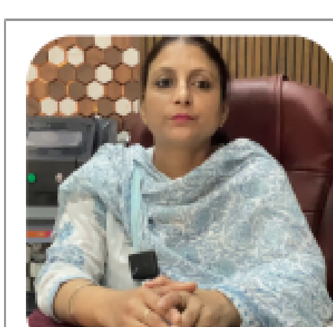
Manpreet Kaur
MK Professional Salon & Academy, Gorakhpur

Dr. Rajesh Singh
Principal, Saraswati Shishu Mandir

Nirmal Yadav
Saraswati Shishu Mandir, Gorakhpur

Amrendra Pandey
Director of SPM Public School, Gorakhpur

Best Wishes for SI News

Deepak Srivastava
Ower of Om Trading Company, Gorakhpur

Kundan Upadhyay
Hindustan News Paper, Gorakhpur

Mayank Rai
Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad

Aditya Shukla
National Student Union of India

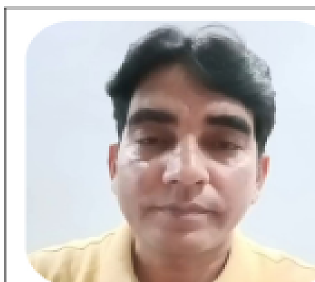
Sanjay Gupta
Asst. Prof. (CS), KIPM College, Gorakhpur

Divyansh Patel
Influencer, Gorakhpur

Pawan Gupta
Press Reporter

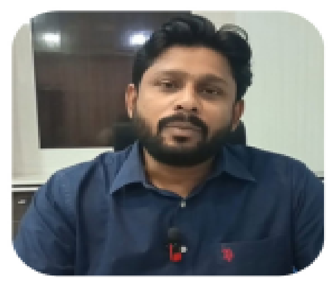
Balram Singh
Dir, Gurukul Enlightened Public School

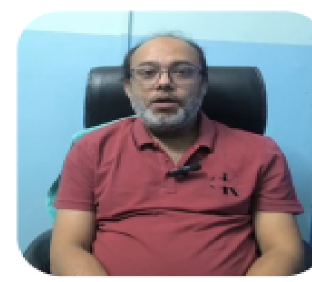
Dr. Shaqib Ahmad
General and Laparoscopic Surgeon

Prabhat Gond
Howk Sports Cricket Academy, Gorakhpur

Abhishek Yadav
Jharkhand Under 23 Cricket Team

Sanjeet Kumar Sangam
Mimicry Artist, Motu Patlu, Bihar

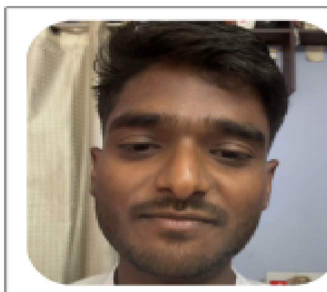
Shivam Patel
Flying Shiva, Sports

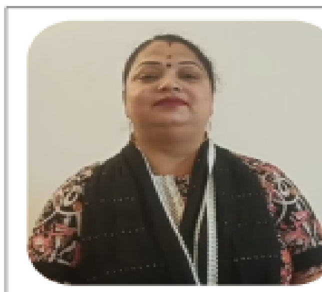
Sangeeta Pandey
Business Enterpreneur, Gorakhpur

Vimal Lohiya
Artist, Green Enviroment, Gorakhpur

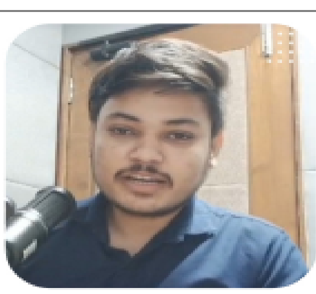
Priyanshu Singh Rathor
Youth Journalist Gorakhpur

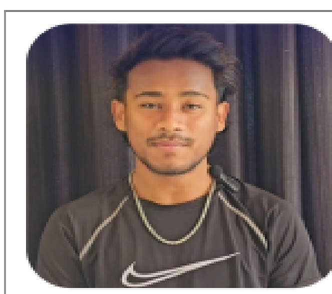
Shubham Gurung
Artist, Influencer Gorakhpur

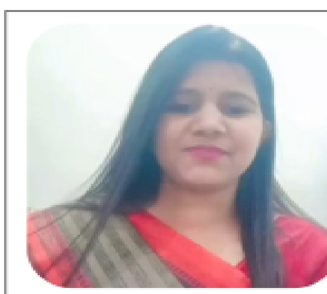
Priya Yadav
Primary, Springer Public School, Gorakhpur

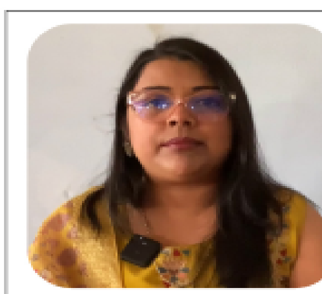
Dr. Vijeta Pandey
Guru Gorakshnath Vridha Ashram

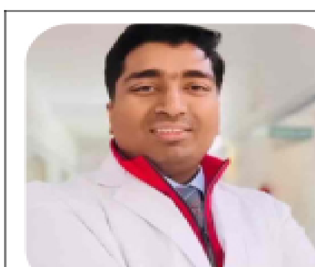
Dr. Srijan Srivastava
SK Dental Clinic, Gorkaphur

Best Wishes for SI News

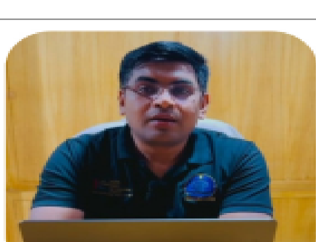
Upendra Singh
SI, Cybercell, Gorakhpur

Ram Vriksh Yadav
TSI, Gorakhpur

Vivek Sonkar
Choreographer, Fusion Dance Academy

Rubee Kori
Artist, Fusion Dance Academy

Ruchi Kori
Artist, Fusion Dance Academy

Dr. Anveshan Singh
MC, DDUGU, Gorakhpur

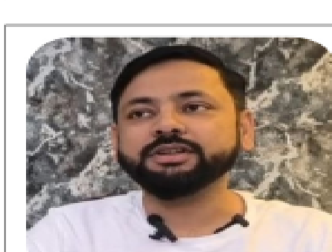
Shoeb Ahmad Khan
Shalimar Electronics (CCTV), Gorakhpur

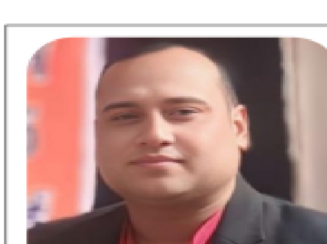
Sushil kumar Singh
Sajag Sarvajan (SS) News Gorakhpur

Ritesh Mishra
President, Press Club Gorakhpur

Dr. Rakesh Pratap Singh
State President of ABVP

सम्पादकीय...

मानव तस्करी पर अंकुश

हरियाणा विधानसभा के मौजूदा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी पहल हुई हैं, जो एक लोककल्याणकारी सरकार की प्राथमिकताएं सुनिश्चित करती हैं। इसमें किसानों को नकली इनपुट से सुरक्षा कवच देना भी सराहनीय कदम रहा है। वहीं हाल ही में सुनहरे भविष्य की आकांक्षा लेकर विदेश जाने वाले युवाओं की हितरक्षा में उठाये गए कदम निश्चय ही सराहनीय हैं। हरियाणा के मौजूदा विधानसभा सत्र में हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वक्त की सख्त जरूरत भी थी। ट्रैवल एजेंसियों के पंजीकरण को अनिवार्य करना और उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान उम्मीद जगाता है कि अब विदेश जाने वाले लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लग सकेगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर सात साल की कैद और पांच लाख रुपये तक के जुमार्ने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से सरकार ने अपने नागरिकों को धोखे और मानव तस्करी से बचाने के लिये एक आवश्यक कदम उठाया है। लगातार होने वाले आव्रजन घोटालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर, इस कानून की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। लेकिन जहां सख्त कानून का सही ढंग से क्रियान्वयन इस दिशा में सफलता सुनिश्चित करेगा, वहीं इसके लिये जन जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। साथ ही प्रभावी प्रवर्तन के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि लोग अनधिकृत एजेंटों के चक्रव्यूह में न फंसें। वास्तव में यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम तो है, लेकिन इसे बेरोजगारी को दूर करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी होना चाहिए। यदि हम राज्य के युवाओं के लिये अपने देश में बेहतर रोजगार के अवसर पैदा कर सकें तो युवाओं को फिर अपने सपने पूरे करने के लिये विदेश जाने की जरूरत ही नहीं होगी। निस्संदेह, कोई भी व्यक्ति अपना घर-परिवार, अपना धार्मिक-सांस्कृतिक परिवेश छोड़कर परदेश नहीं जाना चाहता। लेकिन जब आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार के अवसर नहीं मिलते तो ही वह मजबूरी में विदेश जाने की लालसा रखता है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि बेहतर रोजगार की स्थितियां हमारे शैक्षिक वातावरण पर भी निर्भर करती हैं। यदि हम परंपरागत शिक्षा से इतर रोजगार व कौशल विकास की शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएं तो स्थिति बदल सकती है। इसके लिये जरूरी है कि राज्य में रोजगारपरक शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाया जाए। इस दिशा में गंभीर प्रयासों की सख्त जरूरत है। उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा सत्र में राज्य में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिये उत्साहजनक पहल की जाएगी। इस मुद्दे को प्राथमिकताओं में शामिल करके इस बार गंभीर बहस होगी। दरअसल, हाल के दिनों में कई स्कूलों के भवनों की स्थिति व सुरक्षा आदि को लेकर अभिभावक चिंता जताते रहे हैं। हर अभिभावक चाहता है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर साफ-सफाई, शौचालयों और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहें। दरअसल, देखने में आया है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में छात्रों की संख्या जितनी अधिकता में है, उस अनुपात में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान तो खींचा, लेकिन अन्य राजनीतिक मुद्दों में उलझाव के चलते शिक्षा के मुद्दे पर वैसे गंभीर बहस नहीं हो पायी , जैसी अपेक्षित थी।

राशिफल

मेषः- योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। मस्त-मौला मन ब्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कायरे के प्रति लापरवाह होगा। शिक्षा-प्रतियोगिता की दिशा में किया गया परिश्रम तीव्र होगा।

वृषभः- नयी घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन प्रसन्न होगा। नये कार्य के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। जरूरी कायरे को समय से पूर्ति करें।

मिथुनः- नये क्षेत्रों मे प्रयास से लाभ संभव। समस्याओं के समाधान से उत्साह में वृद्धि होगी। नये संबंधों के सहयोग से आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतें।

कर्कः- सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति में निराशा पैदा करेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। रोजगार में क्षमता का पूर्ण लाभ मिलेगा।

सिंहः- कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाताप संभव। घर में किसी मेहमान के आगमन से व्यय संभव।

कन्याः- मन को सकारात्मक दिशा की ओर केंद्रित करें। भाग्य से प्राप्त अच्छी बुरी सभी स्थितियों के साथ समझौतावादी बने। अपने सुख-दुख छोड़ परिजनों के सुख के बारे में सोचें। आलस्य कतई न करें।

तुलाः- पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए वर्तमान को सुधारें। अच्छे कायरें से परिजनों के दिल में जगह बनायें। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न बरतें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

वृश्चिकः- भौतिक सुख-साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी।

धनुः- मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरें में न जाया करें। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ संभव। संवेदनशील शरीर ग्रहों की प्रतिकूलता से बीमार पड़ सकते हैं। जरूरी कायरे की पूर्ति समय से करें।

मकरः- सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन अरुचि का शिकार होगा। रोजगार में लाभ के नये अवसर मिलेंगे। पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी मेहमान के आगमन से घर में खुशहाल वातावरण रहेगा।

कुंभः- किसी की अस्वस्थता से परिवार में कष्टप्रद माहौल होगा। महत्वपूर्ण कार्यवश घर से दूर जाना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कायरें के प्रति आलस्य न करें। रोजगार में आ रही समस्याओं से निराश न हों।

मीनः- प्रतिभाओं के बावजूद हीन भाव प्रतिभाओं के लाभ से वंचित करेगा। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें।

नो अदर लैंड, तब जाएं तो जाएं कहां?

वर्षा भम्भाणी मिर्जा

तानाशाहों को हमेशा लगता है कि कला जैसे उनके लिए काल बन कर आ रही है। इसलिये वे जब-तब कभी कलाकार पर तो कभी उसके काम पर हमला बोलते रहते हैं। पूरब से पश्चिम तक मामला एक सा ही है। तभी तो तीन सप्ताह पहले ऑस्कर से सम्मानित बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्नो अदर लैंडश के चार निर्देशकों में से एक हमदान बलाल पर सोमवार को उन्हीं के गांव में इजरायली सेना का हमला हो गया। अगले दिन जब उन्हें रिहा किया गया तब उनके सर और शरीर पर चोटों के निशान थे। श्नो अदर लैंडश के चार निर्देशकों में से दो फिलीस्तीनी हैं और दो इजराइली। चार सह-निर्देशकों- बासल अद्रा, हमदान बलाल, युवाल अब्राहम और राहेल सोर की बनाई पहली ही डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता है और पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गई है। नो अदर लैंड डॉक्यूमेंट्री के जरिये इन चारों का मकसद था कि साथ में उनकी आवाज ज्यादा बुलंद होगीय और ऐसा हुआ भी। ऑस्कर समारोह में जब इजरायली पत्रकार युवाल अब्राहम ने अपने फिलीस्तीनी सह-निर्देशक बासल अद्रा की ओर देख कर कहा-जब मैं बासल को देखता हूं, तो मुझे अपना भाई दिखाई देता है, लेकिन हम समान नहीं हैं। हम एक ऐसे शासन में रहते हैं जहां मैं तो आजाद हूं, नागरिक कानून के अधीन हूं लेकिन बासल सैन्य कानूनों के अधीन है जो उसके जीवन को आए दिन नष्ट करते रहते हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। इस बयान ने अभी एक साथ मजबूत आवाज की पैरवी की ही थी कि बलाल पर हमला हो गया और वह चीखता रहा कि मैं मर रहा हूं।ज ये ताकतें नो अदर लैंड को रिलीज होने भी नहीं दे रहीं और ओटीटी मंच इसे हटाने पर मजबूर कर दिए गए हैं। दरअसल नो अदर लैंड वेस्टलैंड के एक हिस्से मसाफिर (मुसाफिर)यत्ता के गांवों की कहानी है जहां बासल अद्रा पैदा हुआ है। दुनिया के नक्शे पर यह जगह मौजूद है जो सात -आठ गांवों से मिलकर बनी है। इजराइल की सेना इस जगह को फौज के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वह इस रास्ते में आने वाले सभी घरों और स्कूलों को बुलडोज कर देना चाहती है। पूरी डाक्यूमेंट्री में सेना के बुलडोजर घर-स्कूल ढहाते नजर आते हैं। घर गिरने के बाद बासल का परिवार गुफाओं में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। विरोध करने पर उसके चाचा को घायल कर दिया जाता है। वह अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच संघर्षरत है। बासल के पास एक कैमरा है और वह सब कुछ शूट करता है। ऐसा लगता है जैसे सेना के हथियार का सामना वह अपने कैमरे से ही कर रहा है। उसका एक ही मकसद है कि उसके इलाके की तकलीफ दुनिया तक पहुंचाए। आखिर यह उसकी जमीन है और उसके पुरखे यहां 1830 से रहते आए हैं। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सप्रमाण जानकारी दी है कि वे उनके कब्जे से पहले यहां रहते आए हैं। धीरे-धीरे ही सही उनकी अवाज को इंटरनेट पर बल मिलता है। एक समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी मसाफिर (मुसाफिर) यत्ता आते हैं। फिर वह सड़क नहीं टूटती, मकान खड़े रहते हैं। कुछ दिनों बाद फिर वही भय के हालात बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री में बासल की मां भी हैं, जो खुद कभी एक्टिविस्ट रही हैं, लेकिन बासल की हताशा और हालात से दुखी हैं। वह दोहराती है कि हमें भी अपनी पहचान चाहिए, हमारे बच्चों को क्यों अच्छी जिन्दगी बसर करने का हक नहीं? दरअसल बासल ने कघनून की पढ़ाई की है लेकिन आर्थिक हालात इस कदर खस्ता हैं कि काम के कोई अवसर नहीं हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी मुलाकात इजराइली पत्रकार युवाल अब्राहम से होती है जो सेना के उत्पीड़न को रिपोर्ट करता है। वह फिल्म में भी उसी बात का जिक्र करता है जो उसने ऑस्कर के मंच से कही थी कि-मैं आजाद नागरिक हूं तो मेरा भाई बासल क्यों नहीं? युवाल से बासल पूछता है - -आप कौन हैं? 00 मैं पत्रकार हूं। -आप अरेबिक हैं? 00 नहीं, इजराइली हूं।-क्या सच? आप क्या मानव अधिकार वाले हो?00 हां कुछ ऐसा ही..-क्या आपको लगता है कि आपका देश सही कर रहा है?00 नहीं, मुझे लगता है यह जुर्म है। सच कहा जाए तो श्नो अदर लैंडश दुनिया के अपनी जमीन से बेदखल कर शरणार्थी बनाए गए तमाम लोगों की कहानी होने के साथ यह इस बात को भी प्रभावी तरीके से बताती है कि लड़ाई जिसके नाम पर लड़ी जा रही है, वे उन हुक्मरानों के साथ नहीं हैं। तभी तो सेना का नुमाइंदा जब युवाल से पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो? इनका साथ क्यों दे रहे हो? तब युवाल कहता है क्योंकि यह सब तुम मेरे नाम पर कर रहे हो, नॉट इन माय नेम। उम्मीद जगाने वाली बात तो यह भी है कि फिलिस्तीन की तकलीफ को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आवाज देने वाले कोई और नहीं बल्कि यहूदी हैं। सभी को याद है कि एक इजरायली फिल्म निर्देशक नदाव लैपिड साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय गोवा फिल्म फेस्टिवल में भारत आए थे और उन्होंने श्द कश्मीर फाइल्सश को श्वल्गर प्रोपेगेंडाश यानी अश्लील प्रचार कहा था। इजराइली फिल्म निर्देशक की इस टिप्पणी से भारत में तूफान आ गया था क्योंकि यह आलोचना सरकारी मंत्री के सामने हुई थी और नरेंद्र मोदी सरकार ने इस फिल्म के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लैपिड बेहद प्रतिभाशाली निर्देशक हैं जिनकी फिल्में बर्लिन और कान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। उनकी फिल्म सिनोनिम्स (पर्यायवाची) को प्रतिष्ठित बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन बेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सिनोनिम्स लैपिड की लगभग आत्मकथात्मक फिल्म है। कथानक का युवा सैनिक इजराइल में जन्मा जरूर है लेकिन वह वहां से भागना चाहता है। वह फ्रांस पहुंचता है।

कुछ खास...

राहुल को क्यों नहीं बोलने देते बिरला?

लगातार तीन बार केन्द्र की सरकार बना लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं, खासकर राहुल गांधी को न बोलने देने पर आमादा है, जो इस बार नेता प्रतिपक्ष भी हैं। पिछली लोकसभा में जब राहुल विपक्ष के नेता नहीं थे और न ही कांग्रेस की सदस्य संख्या आज के जितनी थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनसे खौफ खाते थे और उन्हें चुप कराने के सारे उपाय करते थे। वर्तमान लोकसभा में, जो पिछले साल के मध्य में गठित हुई थी, कांग्रेस की सदस्य संख्या दोगुनी तो है ही, राहुल विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में मोदी का उनसे पहले से दोगुना भय खाना लाजि मी है। बुधवार को तो हद हो गयी जब राहुल अपनी कोई बात कहने के लिये उठे ही थे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही ही स्थगित कर दी। पिछले लम्बे समय से मानो सदन के अध्यक्ष ने यह परिपाटी बना ली है कि राहुल को उनकी बात रखने ही नहीं दी जायेगी। राहुल के बोलने के दौरान अक्सर सत्ता पक्ष के सदस्य शोर-शराबा करते हैं या उनके भाषणों के प्रमुख हिस्से रिकॉर्ड में जाने ही नहीं दिये जाते-खासकर, जब वे मोदी और उनके कारोबारी मित्रों गौतम अदानी तथा मुकेश अम्बानी का उल्लेख करते हैं। पिछली लोकसभा के आखिरी दिनों में तो सरकार उनसे इस कदर भयभीत दिखाई दी कि उनकी सदस्यता तक छीन ली गयी थी। उनका बंगला भी आनन-फानन में खाली करा लिया गया था। उनके खिलाफ एक अवमानना केस तत्काल सुनवाई में लाकर सरकार ने यह प्रबन्ध भी कराया था।

अंततरू अदालती फैसले से उनकी सदस्यता बहाल हुई थी। इसके बावजूद राहुल न झुके, न मोदी तथा भाजपा सरकार पर हमले करना उन्होंने छोड़ा। वे सरकार द्वारा अदानी-अम्बानी को दिये जा रहे संरक्षण को भरपूर उजागर करते हैं और बताते हैं कि मोदी के कारण ये व्यापारी फल-फूल रहे हैं जबकि जनता बेहाल है। बुधवार को संसद भवन के बाहर उन्होंने मीडिया के समक्ष आरोप लगाया कि जब भी वे लोकसभा सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं, उन्हें अपनी बात कहने नहीं दी जाती। बोलने का मौका देने की बजाये ओम बिरला नेता विपक्ष को सदन के नियमों का पालन करने की नसीहत देते रहे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेसी सांसदों द्वारा टी-शर्ट पहनकर सदन में आने पर उन्होंने सदन की मर्यादा व आचरण का पालन करने का आग्रह किया था। उनके अनुसार यह मर्यादा और शालीनता के मानदंडों तथा सदन की परंपरा के प्रतिकूल है। बिरला ने नेहरू-गांधी परिवार का नामेल्लेख किये बगैर ध्यान दिलाया कि इसी सदन में पिता-पुत्री, मां-बेटी और पति-पत्नी सदस्य रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से उन्होंने अपेक्षा की कि लोकसभा प्रक्रिया के नियम 349 के अनुसार वे सदन में आचरण और व्यवहार करें। अध्यक्ष की इस बात से इंकार नहीं है कि मर्यादा तथा शालीनता का सभी को पालन करना चाहिये। सवाल यह है कि ऐसी सारी अपेक्षाएं बिरला साहब केवल विपक्ष से ही करते हैं। जब भाजपा सदस्यों के बोलने की बारी आती है तो उन्हें पूरी छूट मिलती है। उनके बारे में कई बार कहा गया है कि वे दोहरा रवैया अपनाते हैं और भाजपा-सदस्य के रूप में बर्ताव करते हैं। वे खुद विपक्षी नेताओं के भाषणों में अड़ंगा डालते हैं। यहां तक कि सरकार का बचाव भी करते हैं। अक्सर चर्चाओं के उन हिस्सों को काट दिया जाता है जिनमें सरकार की, वह भी जिनमें नरेन्द्र मोदी की आलोचना होती है। बहरहाल, सवाल यह है कि आखिर राहुल से किस बात का सत्ता को खौफ है? कहा जा सकता है कि राहुल की लगभग हर बात से मोदी और उनकी सरकार को डर लगती है। वे जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं या किसी विषय पर अपनी राय रखते हैं, तो वह सरकार को परेशान करने वाली होती है। देश के सारे संसाधनों को कुछ व्यवसायियों को सौंपना, भाजपा सरकारों का अन्याय व भ्रष्टाचार समेत ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सामने लाकर राहुल मोदी का भ्रष्टाचारी व निरंकुश चेहरा सामने ला चुके हैं।

ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ लखनऊ ने खोला जीत का खाता

एजेंसी

नई दिल्ली। शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी के बाद निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की धमाकेदार पारियों की बदौलत लखनऊ सुपर जाएंट्स (एलएसजी) ने पांच विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को हरा दिया। यह लखनऊ की मौजूदा टूर्नामेंट में पहली जीत है। इससे पहले उन्हें दिल्ली ने एक विकेट से करारी शिकस्त दी थी। गुरुवार को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 190 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 16.1 ओवर में पांच विकेट गंवाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। 23 गेंदों के शेष रहते मुकाबला जीतकर लखनऊ ने अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। वहीं, इस मैच से पहले शीर्ष पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद छठे स्थान पर खिसक गई। उनका नेट रनरेट -0.128 हो गया। वहीं, अपने पहले मैच में कोलकाता को सात विकेट से मात देने वाली आरसीबी दो अंक और +2.137 के नेट रनरेट के साथ पहले स्थान पर पहुंच गई। 191 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरूआत झटके के साथ हुई थी। उन्हें पहला झटका मोहम्मद शमी ने एडेन मार्करम के रूप में दिया। वह सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने मोर्चा संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 116 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान पूरन ने 18 गेंदों में अपने करियर का 10वां पचासा जड़ा। उन्होंने 26 गेंदों में 70 रनों दमदार पारी खेली। यह मौजूदा सत्र में उनके बल्ले से निकला दूसरा अर्धशतक है। इसके अलावा मिचेल मार्श ने 52 रनों की दमदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और दो छक्के निकले। हैदराबाद के खिलाफ कप्तान ऋषभ पंत ने 15 और आयुष बडोनी ने छह रन बनाए।

चीन में 'पांडा बॉन्ड' जारी कर पैसे जुटाएगा पाकिस्तान

एजेंसी

नई दिल्ली। आईएमएफ से मदद हासिल करने के बाद अब कर्जे से जूझ रहा पाकिस्तान फिर से चीन पर डोरे डालने लगा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बताया है कि उनका देश पहली बार चीन में पांडा बॉन्ड जारी करने को तैयार है। पांडा बॉन्ड चीन में विदेशी संस्थाओं की ओर से युआन में ऋण हासिल करने का जरिया हैं। इसके जरिए बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों और बीमा कंपनियों को चीनी संस्थाओं से निवेश हासिल करने का मौका मिलता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।आईएमएफ से मदद हासिल करने के बाद अब कर्जे से जूझ रहा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अब ड्रैगन को रिझाने की तैयारी में है। पाकिस्तान चीन के व्यापक पूंजी बाजार का लाभ उठाने के लिए इस साल युआन में पांडा बांड जारी कर सकता है। देश के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने इसकी जानकारी दी है एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, बोआओ फोरम फॉर एशिया के दौरान चीन के सीजीटीएन के साथ एक साक्षात्कार में बोलते हुए औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान चीन के बांड बाजार में कदम रखने के लिए तैयार है। इससे पहले वह केवल पश्चिमी बाजारों में ही ऋणपत्र जारी करता था।

उन्होंने कहा, "मैं वकालत करता रहा हूं और मैं बहुत उत्सुक हूं कि पाकिस्तान... पांडा बॉन्ड की शुरूआत करे।" हमें पूरी उम्मीद है कि इस कैलेंडर वर्ष के दौरान हम ऐसा करेंगे।पांडा बॉन्ड चीन में विदेशी संस्थाओं की ओर से युआन में ऋण हासिल करने का जरिया हैं। वे बैंकों, परिसंपत्ति प्रबंधकों और बीमा कंपनियों सहित चीनी वित्तीय संस्थानों से निवेश हासिल करने का मौका देते हैं। पांडा बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड हो जो चीन के घरेलू बॉन्ड बाजार में विदेशी कंपनियों, सरकारों या वित्तीय संस्थानों की ओर से चीनी मुद्रा युआन में जारी किया जाता है।

तुर्किए की छात्रा को हिरासत में लेने का विरोध

एक और संघीय जज ने रोका ट्रंप का फैसला

हमास के समर्थन का आरोप लगने के बाद मामला में आया नया मोड़

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के टफ्ट्स विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली तुर्किए की एक छात्रा को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने छात्रा पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया। इसके बाद छात्रा को हिरासत में लिए जाने का विरोध शुरू हो गया। छात्रा के वकील, दोस्त समेत तमाम लोगों ने हमास समर्थन के आरोपों को नकारते हुए उसे रिहा करने की मांग की। रुमेया ओतुर्क मंगलवार की रात को अपने दोस्तों से मिलने के लिए सोमरविले स्थित अपने घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे रोक लिया और हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनको लुइसियाना के एक आईसीई हिरासत केंद्र में ले जाया गया। इसे लेकर होमलैंड सुरक्षा विभाग के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि ओतुर्क हमास के समर्थन वाली गतिविधियों में शामिल थी। हालांकि विभाग ने उस समर्थन का सबूत नहीं दिया।वहीं विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि हमने रोज की तरह आज भी ओतुर्क सहित कम से कम 300 लोगों के वीजा रद्द कर दिए। हमने आपको आने और अध्ययन करने और डिग्री प्राप्त करने के लिए वीजा दिया है, न कि एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए, हमारे विश्वविद्यालय परिसरों को नष्ट करने के लिए।छात्रा पर हमास समर्थक होने का आरोप लगने के बाद लोग विरोध में उतर आए। ओतुर्क के दोस्तों ने कहा कि वह विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं थी। वह केवल एक छात्र समाचार पत्र में एक ऑप–एड का सह–लेखन करती है। उसकी दोस्त जेनिफर होयडेन ने कहा कि रुमेया ने केवल थैंक्सगिविंग पोटलक का आयोजन किया था। जो आरोप उस पर लगाए रहे हैं। इसका कोई सबूत नहीं है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग ओतुर्क की रिहाई की मांग को लेकर सोमरविले सिटी हॉल में आए। लोगों ने कउए छापों को लेकर इस्राइल के खिलाफ आवाज उठाई। लोगों ने फलस्तीनियों का समर्थन करते हुए गाने भी गाए। साथ ही नारेबाजी की। लेबनानी अमेरिकी कैरिना कुर्बान ने कहा कि जब

उन्होंने ओतुर्क और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बारे में सुना तो वे क्रोधित हो गईं।कुर्बान ने कहा कि मैं यहीं पैदा हुई हूं। मैं एक अमेरिकी नागरिक हूं, और मुझे उस विशेषाधिकार का उपयोग करने की जरूरत है जो मुझे उन लोगों के लिए बोलने के लिए मिला है जो इस प्रशासन के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण नहीं बोल सकते हैं। अमेरिका मुक्त भाषण पर बनाया गया था, इसलिए यदि हमारे पास वह नहीं है, तो क्या? तो हम कहां जाएं?मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रुमेया ओतुर्क मंगलवार की रात को अपने दोस्तों से मिलने के लिए सोमरविले स्थित अपने घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे रोक लिया और हथकड़ी लगाकर हिरासत में ले लिया।

बलूचिस्तान में अत्याचारों को लेकर घिरा पाकिस्तान, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने लगाए दमन के आरोप

एजेंसी

नई दिल्ली। पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में बढ़ती बगावत को थामने के लिए दमन पर उतर आई है। बड़ी संख्या

में बलोच कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चिंता जाहिर की है और पाकिस्तान की सरकार की आलोचना की है। पाकिस्तान की सेना और पुलिस बलूचिस्तान में अत्याचार कर रही है, लेकिन अब इसे लेकर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घिरता जा रहा है। बलोच यकजेती कमेटी बलोच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जानकारी दे रही है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी पाकिस्तान पर बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन और दमन करने का आरोप लगाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दक्षिण एशिया के निदेशक बाबू राम पंत ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी सरकार द्वारा बलोच कार्यकर्ताओं का दमन किया जा रहा है और उन्हें प्रदर्शन के लिए हिरासत में रखा जा रहा है। इनमें प्रमुख कार्यकर्ता शम्मी दीन बलोच और महरंग बलोच भी शामिल हैं। यह बलोच समुदाय के अधिकारों पर व्यवस्थागत हमला है। पंत ने मांग की कि बलोच कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए और उन्हें बोलने की आजादी का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही उनसे जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच हो। पंत ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल महरंग बलोच और बेबर्ग जहरी के परिजनों से मिली रिपोर्ट्स को लेकर चिंतित है। बेबर्ग को दिव्यांग होने के बाद भी चिकित्सीय मदद नहीं दी जा रही है, जबकि हिरासत में उनकी हालत लगातार खराब हो रही है। एमनेस्टी ने कहा कि पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियां बलोच लोगों के मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन कर रही हैं।

ट्रांसजेंडर्स को सेना में प्रतिबंधित करने की नीति पर लगाई रोक

एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिका के एक और संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति पर रोक लगा दी है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स लोगों को सेना से प्रतिबंधित कर दिया गया था। गुरुवार को यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज बेंजामिन सेटल ने यह आदेश दिया। इस आदेश से सेना में सेवा दे रहे कई ट्रांसजेंडर्स सैनिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन की नीति

उनके प्रति अपमानजनक और भेदभावपूर्ण है और उन्हें नौकरी से निकाले जाने पर उनके करियर और प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही अमेरिका की एक अन्य संघीय न्यायाधीश एना रेयेस ने भी ट्रंप प्रशासन के ट्रांसजेंडर्स को सेना से प्रतिबंधित करने की नीति पर रोक लगा दी थी। अब ताजा आदेश से अमेरिकी वायुसेना में सेवा दे रहे दो ट्रांसजेंडर पुरुषों को नौकरी से निकाले जाने पर भी रोक लग गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद 27 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया कि ट्रांसजेंडर्स की लैंगिक पहचान सैनिकों के अनुशासन, सम्मान के आड़े आती है और यह सेना की तैयारियों के लिहाज से खतरनाक है। इसके बाद ट्रांसजेंडर्स लोगों को सेना से प्रतिबंधित कर दिया गया।अदालत में ट्रंप की नीति के खिलाफ जेंडर जस्टिस लीग नामक संगठन ने याचिका दायर की थी, जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती है। उल्लेखनीय है कि साल 2016 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने ट्रांसजेंडर्स को सेना में सेवा देने की मंजूरी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रांसजेंडर्स को सेना में सेवा देने से रोकने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जो बाइडन के सत्ता में आने के बाद इसे रोक दिया गया। अमेरिका के एक संघीय जज ने गुरुवार को सिग्नल एप पर साझा किए गए संदेश संरक्षित करने का आदेश दिया है। दरअसल सिग्नल एप पर बीते दिनों अमेरिकी सरकार के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों ने हूतियों पर हमले की खुफिया जानकारी साझा की थी, जो लीक हो गई। इस लीक के बाद ट्रंप प्रशासन अपने आलोचकों के निशाने पर है। एक गैर लाभकारी संस्था अमेरिकन ओवरसाइट ने संदेशों को संरक्षित करने की मांग की थी। अमेरिका की एक पत्रिका में उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, खुफिया विभाग की निदेशक, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि, सीआईए निदेशक समेत कई शीर्ष नेताओं और अधिकारियों की खुफिया और संवेदनशील बातचीत का पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया था।

पूर्व राष्ट्रपति मार्टिनेली को निकारागुआ दूतावास छोड़ने की अनुमति

एजेंसी

नई दिल्ली। पनामा के पूर्व राष्ट्रपति मार्टिनेली को मनी लॉड्रिंग के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया था। तब से वे निकारागुआ के दूतावास में छिपे हुए थे। पनामा के पूर्व राष्ट्रपति रिकार्डो मार्टिनेली को निकारागुआ दूतावास छोड़ने की अनुमति मिल गई है। अब वे निकारागुआ के शहर में जाकर रह सकेंगे। मनी लॉड्रिंग मामले में सजा पाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति पिछले एक साल से दूतावास में छिपे थे। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज–आचा वास्केज ने कहा कि दूतावास छोड़ने के बाद निकारागुआ जाकर मार्टिनेली परिस्थितियों में अपना कानूनी बचाव कर सकेंगे।

युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमंत्री शर्मा

एजेंसी

नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार हर खिलाड़ी को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने वर्ष 2024-25 में 1614 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। शर्मा ने राजस्थान दिवस समारोह के तहत रन फॉर फिट राजस्थानदौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी दौड़ में शामिल होकर प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उन्होंने इस अवसर पर कहा

कि फिटनेस केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि हमने फिट राजस्थान अभियान शुरू करने का संकल्प लिया था, रन फॉर फिट राजस्थान इसी संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार के साथ भूखंड आवंटन, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं।

राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना...

भाई-भतीजावाद और कुप्रबंधन ने बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बैंक के कुछ कर्मचारियों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने इस मुलाकात का एक वीडियो एक्स पर साझा किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के भाई-भतीजावाद और नियामक कुप्रबंधन ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक निजी बैंक के कुछ कर्मचारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने भाजपा पर बंकिंग क्षेत्र को संकट में डालने जैसा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के भाई-भतीजावाद और नियामक कुप्रबंधन ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को संकट में डाल दिया है, जिसके चलते जूनियर कर्मचारियों को तनाव और तनावपूर्ण कार्य स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

साथ ही राहुल गांधी ने भाजपा पर अपने अरबपति मित्रों के लिए 16 लाख करोड़ रुपये के ऋण माफ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत हजारों ईमानदार कामकाजी पेशेवरों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी बैठक का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कर्मचारी बता रहे थे कि बैंक में कुप्रबंधन के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी इन कामकाजी पेशेवरों

के अधिकारों के लिए लड़ेगी और उनके कार्यस्थल पर अतरिक्त तनाव को समाप्त करने की कोशिश करेगी।

हुक्का बार प्रकरणः गैंग चार्ट तैयार, आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर

संवाददाता

गोरखपुर। हुक्का बार प्रकरण में सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पुलिस ने गैंग चार्ट तैयार कर लिया है। डीएम की स्वीकृति के लिए गैंग चार्ट भिजवाया जाएगा। एक सप्ताह में पुलिस प्रक्रिया पूरी होने का दावा कर रही है। इस केस में होटल संचालक व कर्मचारियों समेत अभी पांच और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी है। सभी आरोपी भागे हुए हैं। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एनबीडब्ल्यू लेकर इनाम

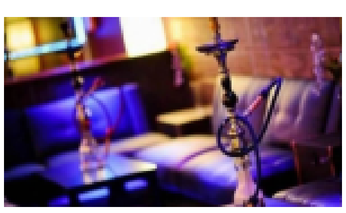

रखने की तैयारी में जुटी है। दरअसल, शाहपुर थाना क्षेत्र में गीता वाटिका के पास फ्लाई इन होटल में संचालित जीनस बॉटल रेस्टोरेंट में हुक्का बार का संचालन हो रहा था। पुलिस ने यहां छापा मारा तो देह व्यापार की बात सामने आई। जांच में पता चला कि फ्लाई इन होटल का संचालक अनुराग सिंह, हुक्का बार संचालक अनिरुद्ध ओझा के साथ मिलकर देह व्यापार का एक बड़ा गिरोह चला रहा है। पुलिस सरगना अनिरुद्ध ओझा, फ्लाइ इन होटल का मालिक अनुराग कुमार सिंह, मोहनापुर का आकाश यादव, बिछिया के रोहित छेत्री और विनय साहनी, आदित्य मौर्या और निखिल सिंह, बस्ती मुंडेरवा के उमरी अहरा निवासी राजन उर्फ वसीम अहमद, हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के बरवा सरसंड का विमल विश्वकर्मा और सूरज विश्वकर्मा, रेशमा खान, नंदनी शर्मा, मुस्कान, श्रेय शुक्ला और अजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है।

70 कॉलेजों ने अपलोड नहीं किए आंतरिक मूल्यांकन के अंक, नोटिस जारी

संवाददाता

गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में अप्रैल से सम सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन अभी तक कुछ कॉलेजों ने विषम सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के अंक अपलोड नहीं किए हैं। इसकी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने करीब 70 कॉलेजों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उन्हें जल्द अंक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कॉलेजों की ओर से अंक अपलोड न करने की वजह से स्नातक के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हो सका है। जिन कॉलेजों ने अंक अपलोड किए हैं, उनका परिणाम जारी हो गया है। परास्नातक प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के ज्यादातर विषयों के परिणाम घोषित भी हो गए, लेकिन कॉलेजों में स्नातक (बीए, बीएससी और बीकॉम) के परिणाम अब तक अघोषित है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विषम सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले ही कॉलेजों को निर्देश दिया था कि वे आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दें। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद रिमाइंडर पर रिमाइंडर दिए जाते रहे, लेकिन कॉलेजों ने अंक अपलोड करने में शिथिलता बरती।

लखनऊ। जानकीपुरम प्रथम सीता विहार कॉलोनी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह महापौर सुषमा खार्कवाल के सहयोग से लोकप्रिय विधायक डॉ० नीरज बोरा पार्षद सौरभ तिवारी के वार्ड विकास निधि से सुरेंद्र सिंह के मकान से शुक्ला मकान तक रोड़ का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ मंडल अध्यक्ष संजय तिवारी पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे भारतीय बारी समाज प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक बारी सुभाष पांडेय कार्यकर्ता, एवं स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

2.53 करोड़ से पॉवर ट्रांसफार्मरों की हो रही देखभाल, फॉल्ट से मिलेगी राहत

संवाददाता

गोरखपुर। गर्मी में उपभोक्ताओं को बिजली फॉल्ट से राहत देने के लिए बिजली निगम ने तैयारी कर ली है। शहर में 28 बिजली घरों के 63 पॉवर ट्रांसफार्मर की देखभाल व अन्य सामग्री बदलने के लिए एमडी विवेकाधीन कोष से लगभग 2.53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पॉवर ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य चल रहा है। इस व्यवस्था से शहर के उपभोक्ताओं को गर्मी के मौसम में राहत मिलेगी। पॉवर ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो जाने से इसमें जल्दी खराबी नहीं आएगी। साथ ही बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। इसके तहत करंट ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है।

पुराने वैक्यूम सर्किल ब्रेकर को बदलने व जहां यह खराब है वहीं दूसरा लगाने का कार्य चल रहा है। कंट्रोल पैनल के साथ पॉवर ट्रांसफार्मर पर लाइटिंग अरेस्टर भी लगाया जा रहा है। फ्यूसेट भी जहां नहीं था वहां लग रहा है। बताया जा रहा है कि उपकेंद्रों में पॉवर ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखने व 33 केवी की लाइन को काटने के लिए उपकेंद्रों पर स्विच लगाए जा रहे हैं। जिससे पॉवर ट्रांसफार्मर की लाइट आवश्यकता पड़ने पर उपकेंद्र से ही काट दी जाएगी। इससे तत्काल खराब ट्रांसफार्मरों को ठीक किया जा सकेगा। पॉवर ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा व देखभाल को लेकर कार्य चल रहा है, कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा भी हो चुका है।

मनीष कनौजिया
भाजपा सक्रिय सदस्य
मध्य विधानसभा

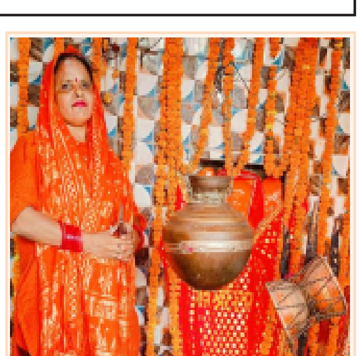

प्रत्याशी गुड़िया
पूर्व सभासद कनौजिया
राजा बिहार वार्ड मध्य
विधानसभा लखनऊ

उ0 प्रे0 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ कलेक्ट्रेट अध्यक्ष गिरजा शंकर वर्मा कार्यवाहक अध्यक्ष अवनीश कुमार राणा महामंत्री मजार खान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश सिंह कार्यालय संरक्षक सुफियान खान

'This is absolute breakdown of rule of law'

Supreme Court slams UP Police for converting civil cases into criminal offences

New Delhi | The Supreme Court Monday pulled up the Uttar Pradesh Police for filing criminal charges in what it said was primarily a civil dispute for allegedly not returning Rs 25 lakh borrowed from a person. The apex court was hearing an appeal challenging the Allahabad High Court decision dismissing the plea to quash FIR against petitioners Debu Singh and Deepak Singh facing charges of criminal breach of trust, criminal intimidation, and criminal conspiracy. "This is wrong what is happening in UP. Every day in and day out, civil matters are being converted into criminal... This is an absolute breakdown of the rule of law," Chief Justice of India Sanjiv Khanna presiding over a three-judge bench said. The bench, also comprising Justices Sanjay Kumar and K V Viswanathan, said this was contrary to its direction in the case of Sharif Ahmed vs State of Uttar Pradesh wherein it laid down that the investigating officer must ensure that the chargesheet contains clear and complete entries of all columns in the chargesheet so that the court can clearly understand which crime has been committed by which accused and what is the material evidence available on the file. "The order taking cognisance, the summoning order as well as the chargesheet filed is clearly contrary to the decision in Sharif Ahmed and others Vs State of UP. In view of this, we would require the Director General of Police of UP as well as the Station House Officer/ Investigation Officer of the police station to file an affidavit showing compliance with the directions given in the judgment," the bench said in the order. The bench directed that the affidavit be filed within two weeks, and ordered that "the proceedings in trial court will remain stayed against all accused". "Proceedings under section 138 of the Negotiable Instruments Act, which are not the subject matter of the present petition, shall continue," said the bench. As per the prosecution, the petitioners' father, Baljeet Singh, who had a scrap business, had borrowed Rs 25 lakh from one Deepak Behl in their presence. Subsequently, Baljeet Singh refused to return the money at the promised time, and when Behl demanded it back, he allegedly threatened, saying he and his sons would burn him alive.

'Adversely affects interests of Muslims'

Chennai | DMK moves SC against Waqf Filed by DMK deputy general secretary and MP A 2025 moved by the Hon'ble Chief Minister in the Tamil Nadu Legislative Assembly urging the Union Government to withdraw the Waqf (Amendment) Bill, 2025 as it was unconstitutional and adversely affected the rights and interests of the Muslim minority community," the statement said. Despite opposition from members of the

AmendmentIn a statement, the party said the DMK government, under the leadership of Chief Minister M K Stalin, has consistently worked for the socio-economic upliftment of minorities and backward classes. Tamil Nadu's ruling party, the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), on Monday filed a writ petition before the Supreme Court challenging the constitutional validity of the Waqf (Amendment) Act, 2025, signalling a serious escalation in the party's opposition to the central legislation that it says undermines minority rights. Raja, who also serves on the Joint Parliamentary Committee (JPC) on the Waqf Bill, the petition contends that the amendments to the Waqf Act, 1995, infringe upon the fundamental rights of the Muslim community. The petition has been settled by senior advocate P Wilson. In a statement, the party said the DMK government, under the leadership of Chief Minister M K Stalin, has consistently worked for the socio-economic upliftment of minorities and backward classes. "The DMK Government had passed a resolution dated 27 March, JPC and various stakeholders, the amendment was passed by Parliament and notified on April 6. The DMK has claimed that critical objections raised in Parliament were not addressed. The DMK said the party chose to fight it legally as the immediate implementation of the Act infringes and prejudices the rights of about 50 lakh Muslims in Tamil Nadu and 20 crore Muslims in other parts of the country. The move follows CM Stalin's announcement on April 3 in the state Assembly that the DMK would approach the Supreme Court.

US stocks tumble for third straight day, S&P 500 falls into bear market

New Delhi:Even as Indian stock markets plunged 5 per cent, US markets suffered another brutal blow on Monday, plunging for the third consecutive session, as President Donald Trump's aggressive tariff strategy sent shockwaves through Wall Street. The Dow Jones Industrial

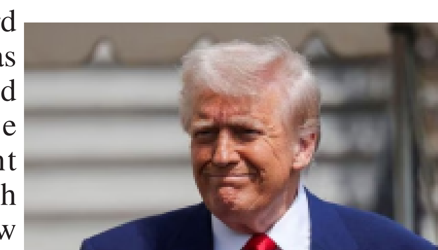

Average sank another 1,363 points, extending a historic losing streak that began late last week. This follows back-to-back 1,500-point losses on Thursday and Friday — a first in market history. S&P 500 enters bear territory: The S&P 500 tumbled 4 per cent on Monday, pushing its three-day slide to around 13 per cent, the steepest such drop since the 2008 financial crisis. The Nasdaq Composite, already in bear market territory, fell an additional 4 per cent, extending its losses to 26 per cent from its previous peak. Tech stocks, once seen as market darlings, were among the hardest hit as investors scrambled for cash. Market in turmoil: At the centre of the storm is the White House's decision to impose a sweeping 'reciprocal' tariffs on major trading partners of the US. President Trump has defended the move, stating, "Sometimes you have to take medicine to fix something." Trump imposed sweeping new tariffs on all trading partners causing global market turmoil and swift condemnation from allies and adversaries and tit-for-tat retaliation from China. All countries have been slapped with a 10 per cent 'baseline' tariff, with several others hit with varying levels of 'retaliatory' tariffs. Trump insists the policy will deliver "historic" results — but global businesses are already feeling the pressure.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, शक्ति शंकर द्वारा फाईन आफसेट प्रिंटर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्शीपुर, जनपद–गोरखपुर से मुद्रित कराकर, मुहल्ला–द्वितीय तल पुष्पांजलि काम्प्लेक्स शाही मार्केट, गोलघर, जनपद–गोरखपुर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक :
शक्ति शंकर
मो नं.
7233999001

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र गोरखपुर न्यायालय होगा।